

गहलोत सरकार का कोविड प्रबंधन उत्कृष्ट है: नये-नये तरीके ढूँढ़े गये चहेती कंपनियों से लूट मचवाने के लिए

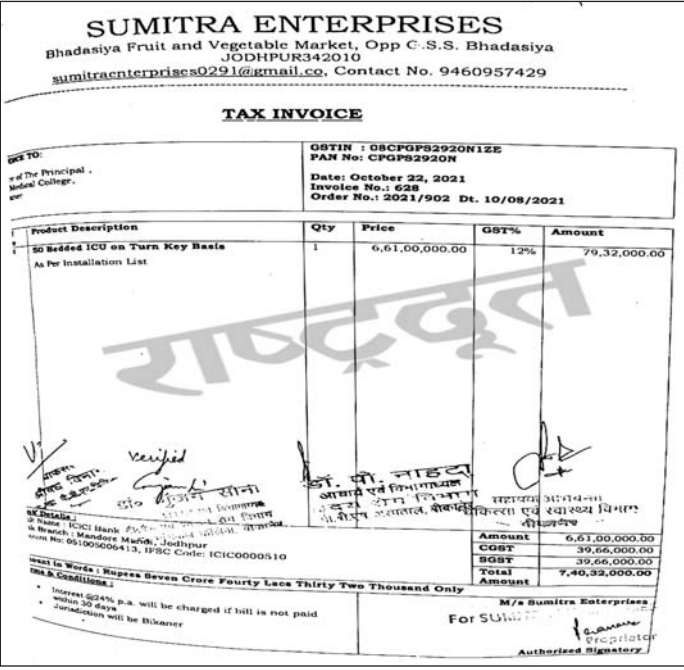
उदाहरण के लिए, एसएमएस अस्पताल को अधिकृत किया गया, राज्य के सभी अस्पतालों के लिये वैंटीलेटर खरीदने के लिये

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 21 अप्रैल। गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान कोविड महामारी के चलते स्टेट डिज़ास्टर रिस्केशन फंड (एस.डी.आर.एफ.) से आई.सी.यू. इत्यादि जैसे स्थाई निर्माण ही नहीं किये गये, बल्कि चिकित्सा विभाग के वित्त सलाहकारों ने नियमों की अनदेखी करते हुए इन आई.सी.यू. व बच्चों के लिये बने एन.आई.सी.यू. और पी.आई.सी.यू. के निर्माण कार्यों को “टर्नकी” प्रोजेक्ट की तर्ज पर शुरू करने की अनुमति भी दे दी, जिसके कारण इन आई.सी.यू. में लगाये जाने वाले उपकरणों की खरीद में भी भारी धांधली हुई।

दरअसल कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद पर केन्द्र सरकार ने टैक्स में भारी कटौती की थी, इसके तहत जी.एस.टी. 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई थी, परंतु यह छूट टर्नकी प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं की जा सकती। पर हैरानी की बात है कि एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति ने पूरे प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में वैंटीलेटर, ई.सी.जी. मशीन, वॉर्मर इत्यादि खरीदे लेकिन महंगी दरों पर और सप्लायरों की तरफ से 12 प्रतिशत जी.एस.टी. भी अदा किया।

यही नहीं एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति ही पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिये मेडिकल उपकरण खरीद के आदेश दे रही थी, जबकि उन्हें किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओर से



प्रकाशित दस्तावेज एक टैक्स बिल है जिसमें देखा जा सकता है कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज में सुमित्रा एन्टरप्राइजेज नामक एक फर्म से 50 बिस्तर के आई.सी.यू. में “टर्नकी प्रोजेक्ट” के माध्यम से मेडिकल उपकरणों को लगाने का अनुबंध किया गया था। इस कंपनी द्वारा मेडिकल उपकरण लगाने के लिये मेडिकल कॉलेज से 12 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी. वसूला गया। जैसा कि विदित है कि कोविड के दौरान केन्द्र सरकार ने मेडिकल उपकरणों की खरीद पर जी.एस.टी. की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी थी, परंतु गहलोत सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नियम और नीति के विरुद्ध जाते हुए एस.डी.आर.एफ. से घटिया दर्जे के आई.सी.यू. का निर्माण कराया और मेडिकल उपकरण की खरीद में भी भारी धांधली की।

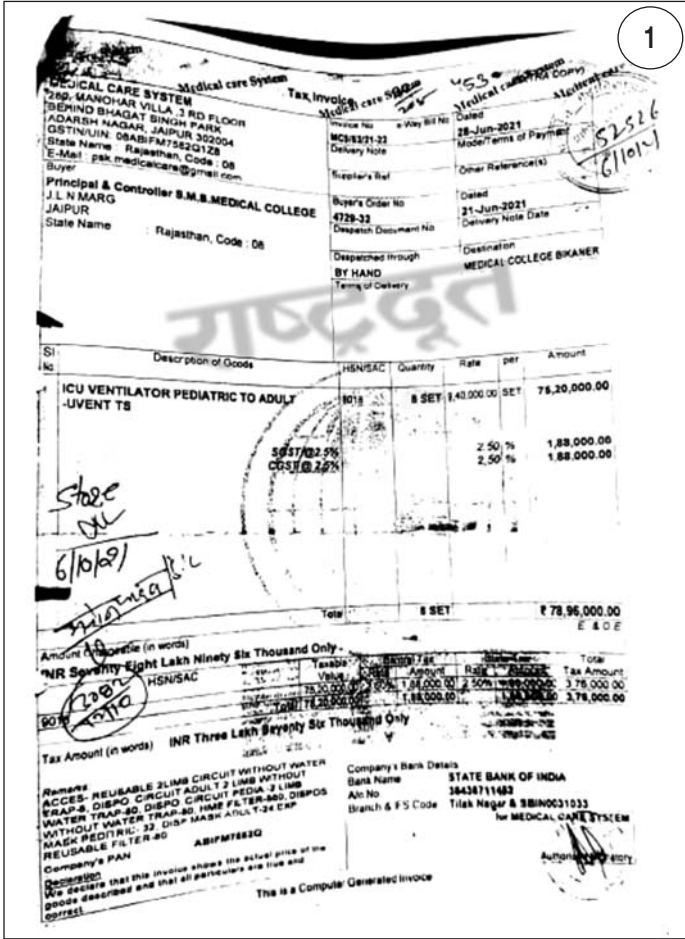
■ पर, किस अस्पताल को कितने वैंटीलेटर चाहिए अपने आईसीयू के लिए, इस बारे में अस्पतालों से न तो पूछा गया और न ही कोई बातचीत की गई।

■ जैसा कि खबर के साथ प्रस्तुत बिलों की प्रतियों से नज़र आता है। एसएमएस अस्पताल के लिये जिन दामों पर वैंटीलेटर खरीदे गये, उससे लगभग दोगुने दामों पर प्रदेश के अन्य अस्पतालों के लिए वैंटीलेटर खरीदे गये, यह एक्स्ट्रा पेमेंट किस को मिला?

■ वैंटीलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी को जीएसटी का पूरा लाभ दिलाने की दृष्टि से वैंटीलेटर केन्द्रीय सरकार की नीति व आपदा प्रबंधन निधि से खरीददारी नहीं की गई। अगर केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के अनुसार खरीद की जाती तो जीएसटी 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत ही लगती। ऐसे “सुप्रबंधन” के कई नायाब तरीके ढूँढ़े गये और सप्लायर को लाभान्वित किया।

■ गहलोत सरकार के अधिकारी कुछ गिनी चुनी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद का बल्क ऑर्डर ना देके अलग-अलग खरीद के आदेश पारित कर रहे थे। इसका स्पष्ट प्रमाण एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस पी मैडिकल कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। जहां एक ओर वैंटीलेटर 9 लाख रुपये की दर पर खरीदे गये वहीं दूसरी ओर लगभग दुगुनी लागत पर खरीदे गये।

उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव नहीं सौंपा गया था। हालांकि यह भी सत्य है कि महामारी के दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिये निविदा जारी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता (आर.टी.पी.पी.) अधिनियम निर्बंधित था परंतु राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मेडिकल उपकरणों की खरीद आर.एम.एस. सी.एल. के माध्यम से की जा सकती थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



लालू-राबड़ी व नीतीश का युग समाप्ति की ओर अग्रसर

पोप फ्रांसिस का निधन



वैटिकन, 21 अप्रैल। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का ईस्टर सोमवार को वैटिकन के कासा सांता मार्टा में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। होली सी (रोमन कैथलिक चर्च की

■ 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस ने वैटिकन के कासा सांता मार्टा में अपने निवास पर अंतिम सांस ली।

सरकार) ने आज यह जानकारी दी। होली सी ने एक्स पर लिखा, पोप फ्रांसिस का निधन ईस्टर सोमवार को 88 वर्ष की आयु में वैटिकन के कासा सांता मार्टा में उनके निवास पर हुआ। वैटिकन के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सुबह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा से हिन्दुस्तान के लिए खिड़की तो खुली, ट्रम्प तक बात पहुंचाने के लिए

इस समय अमेरिका, यूरोपियन यूनियन व चीन, दोनों से “लगभग” शत्रुता के रिश्ते बनाये हुए हैं और बातचीत बंद सी है। अतः भारत के पास अपना पक्ष सुनाने का अच्छा मौका है

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की आज की भारत यात्रा, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है।

सबसे पहले, इस यात्रा में एक व्यक्तिगत पहलू है, जो उनकी पहली यात्रा के बारह साल बाद हो रही है। इस व्यक्तिगत जुड़ाव के बयान के साथ, वैंस की भारत यात्रा इस बात को स्पष्ट करती है कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत में अपने शुरुआती कार्यक्रमों के तहत, उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया, जहाँ वैंस के बच्चों ने भारतीय परिधान पहन रखे थे और उनके गले में फूलों की मालाएँ थीं। इससे अमेरिका की “सैकण्ड फैमिली” और भारत के बीच सांस्कृतिक और व्यक्तिगत

■ पर, जैसा ट्रम्प का स्वभाव है, अगर इनमें से किसी से भी बातचीत शुरू हुई तो ट्रम्प भारत का साथ छोड़कर, इन दोनों से सौदेबाजी शुरू कर देंगे, क्योंकि अपने साइज़ व आर्थिक ताकत के कारण, ये दोनों भारत से ज्यादा महत्व रखेंगे, ट्रम्प की निगाह में।

संबंधों का गहरा संकेत मिला।

दूसरा संकेत मिला कि भारत, अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश को एशिया में तथा समग्र भू-राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक मजबूत दीवार के रूप में देखा जाता है। अमेरिका चीन को अपना प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मानता है, आर्थिक रूप से भी और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से भी।

गौरतलब है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय दक्षिण-पूर्वी एशिया के एक लंबे दौरे पर हैं, जहाँ वे एक ऐसा राष्ट्र-गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिका के विरुद्ध चीन के साथ खड़ा हो सके। अभी हाल तक, दक्षिण-

पूर्वी एशियाई देश लगभग अमेरिका के सहयोगी देश ही माने जाते थे।

अब चीन इन देशों को, चीन के विशाल बाजारों में आकर्षक सुविधाओं का लालच देकर अमेरिका से दूर करने की कोशिश कर रहा है। चीन इन देशों को यह दिखाता चाहता है कि अमेरिका की तुलना में वो कहीं ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर है। इस तरह से, चीन एशिया में, और अन्य जगहों पर भी, अमेरिका को उसके सहयोगियों से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है।

कई मायनों में, अमेरिका पहले से ही वैश्विक मंच के प्रमुख खिलाड़ियों से थोड़ा अलग-थलग हो गया है। ट्रंप

प्रशासन ने चीन और यूरोपीय संघ, जो आर्थिक और रणनीतिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्लाक हैं, को बुरी तरह आहत किया है।

वैंस बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जैलेंस्की के साथ डॉनबेड ट्रंप की कुख्यात बैठक में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। वैंस, ट्रंप के विश्वासपात्र हैं, हालांकि, ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री को यात्रा के दौरान वैंस को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था।

इस प्रकार, भारत के पास यह अवसर है कि वह अमेरिका को अपनी स्थिति समझा सके, खासकर ऐसे समय में, जब अमेरिका ने अपनी टैरिफ की बाढ़ के जरिए प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ एक प्रकार का व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। भारत को भी तथाकथित “रैसिप्रोकल टैरिफ” का सामना करना पड़ा है, जिसे वर्तमान में 90 दिनों के लिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जेल प्रहरी पेपर लीक के आरोपी को जमानत नहीं मिली

जयपुर, 21 अप्रैल। जयपुर मेट्रो-प्रथम की डीजे कोर्ट ने जेल प्रहरी भर्ती-2018 के पेपर लीक मामले के आरोपी करन कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए, आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। डीजे नंदिनी व्यास ने फैसले में कहा कि मौजूदा मामले में

■ अदालत ने कहा, आरोपी लंबे समय से अनुसंधान के लिये उपस्थित नहीं हो रहा है, इसलिये जमानत नहीं दी जा सकती।

आरोपी को लंबे समय से अनुसंधान के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। उसकी तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई, जिस कारण केस के अनुसंधान में भी देरी हुई है। मामला सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ा है और ऐसे मामले के आरोपी को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘वैंस की भारत यात्रा से हिन्दुस्तान की टैरिफ संबंधी चिंताएँ घटेंगी नहीं’

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। क्या अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की भारत यात्रा से वाशिंगटन की टैरिफ नीति पर नई दिल्ली की चिंताएँ कम होंगी? बीजिंग का कहना है, ऐसा नहीं होगा। बीजिंग ने यात्रा के परिणामों और उद्देश्यों को बहुत हल्के रूप में लिया है।

चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, वैंस की चार दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के बीच के आर्थिक अवसरों को अनलॉक करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों के बीच हुई है। लेकिन भारत और चीन के विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि इस यात्रा से अमेरिका के कथित “रैसिप्रोकल टैरिफ” पर भारत की चिंताओं में कोई राहत नहीं मिलेगी और न ही इससे भारत की व्यापार नीति में कोई निर्णायक बदलाव होगा।

अपनी अधिकृत कृतीति को “पर्सनल टच” देते हुए, वैंस अपनी पत्नी ऊषा वैंस, जो हिंदू हैं और बच्चों के साथ

दौर के बाद, ऐसी संभावना हो सकती है कि आगामी चुनावों के बाद, बिहार में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत आए हैं। उनके साथ अमेरिकी प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। ये सभी दिल्ली, जयपुर और आगरा जाएंगे तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन्हें एक रात्रिभोज देंगे। संभावना है कि वार्ता का फोकस लम्बे समय से विचारार्थीन ट्रेड पैक्ट होगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के नए मुकाम तलाश करने पर होगा। वैंस के साथ अमेरिका के 5 टॉप अधिकारियों हैं, जिनमें पेंटागन और विदेश विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

यह वैंस की पहली भारत यात्रा है और चीनी पर्यवेक्षक इसके रणनीतिक संकेतों के बारे में बात करते हुए कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। विशेषज्ञों का

■ अमेरिका के टैरिफ वॉर का मकसद है, अमेरिका में काम आने वाली ज्यादा से ज्यादा चीज़ें अमेरिका में ही निर्मित हों तथा अमेरिका विश्व का “मैन्यूफैक्चरिंग हब” (औद्योगिक उत्पादन का केन्द्र) बने।

■ दूसरी ओर भारत का “मेक इन इण्डिया” का सोच भी, हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने की दिशा को ही सही मानता है।

■ अतः, उपराष्ट्रपति वैंस की भारत यात्रा एक गुडविल (सद्भावना यात्रा) तक ही सीमित रहेगी और कोई ठोस लाभ नहीं मिलेगा, भारत को “टैरिफ वॉर” में।

मत है कि यह यात्रा सावधानीपूर्वक तैयार की गई सोची समझी रणनीति है, जिसमें कृतीति और पारिवारिक जुड़ाव का मिश्रण है और इसका उद्देश्य टैरिफ के

कारण यूएस के अपने सहयोगियों के साथ उपजे तनाव के समय में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करना है, लेकिन बीजिंग में कुछ ही विशेषज्ञ मानते हैं कि यह यात्रा भारत को अनुसुलझे टैरिफ विवाद से राहत देगी।

शिन्हुआ विश्वविद्यालय के नेशनल स्ट्रैटजी इंस्टीट्यूट के निदेशक कियान फेंग का कहना है कि वैंस कई उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं। द्विपक्षीय ट्रेड पैक्ट से लेकर टैरिफ विवादों के हल तक पर फेंग ने चेतावनी दी कि ठोस नतीजे मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि वाशिंगटन का सारा जोर व्यापार घाटा कम करने और निर्माण गतिविधियों को अमेरिका वापस लाने पर है। यह रणनीति “मेक इन

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी का नाम सीबीआई कोर्ट की 32 पृष्ठ की रिपोर्ट में है। कमलेश प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर में उनकी व उनके भाई मनीष चौधरी की भूमिका की जांच की मांग की गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फर्जी

इंडिया” के खिलाफ है। हालांकि, कुछ प्रगति हुई है, जैसे 29 मार्च को अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधियों व भारत के वाणिज्य मंत्रालय के बीच 2030 तक व्यापार 500 बिलियन डॉलर पहुँचाने के लक्ष्य पर समझौता हुआ, पर अभी भी कई बाधाएँ हैं।

इस पृष्ठभूमि में विश्लेषकों का कहना है कि वैंस संभवतः भारत को वाशिंगटन के उद्देश्यों के बारे में पुनः आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे तथा टैरिफ के लचीलेपन को प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि भारत ऐसी कोई रियायत देने के मूढ़ में नहीं है, जो उसकी घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग में कटौती करे, तथा अमेरिकन टैरिफ नीतियों की प्रस्तावित रियायतों पर आँखें मूंद कर भरोसा करे।

बीजिंग एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के एसोसिएट रिसर्च फेलो वांग पेंग ने कहा है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच के टैरिफ-जन्य तनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ सीबीआई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में हरीश के खिलाफ जाँच के आदेश दिये।

मुठभेड़ और प्रजापति की हत्या का केस सीबीआई को सौंपा था। सवाल यह है कि क्या यह गहलोत की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की आखिरी जीत है।

इसी सीबीआई कोर्ट ने इस प्रकरण में हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी और 2 आईपीएस अफसर सहित, 24 पुलिस अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)